

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी- डॉ० एस.पी.सिंह (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या- 168/17

बउनवान

देवलाल आयु 80 साल पुत्र जगन्नाथ जाति-गुर्जर निवासी-भडसुई
तहसील-बारां, जिला-बारां (राज०)

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार, बारां

(रेस्पोंडेंट)

अपील धारा-75 भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :-1. श्री नन्दकिशोर गुर्जर, अभिभाषक

(अपीलांट)

2. परोकार सरकार

(रेस्पोंडेंट)



निर्णय दिनांक- 30.07.2018

अपीलांट ने जयें अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 08.10.2015 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा-75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम-भडसुई, तहसील-बारां की आराजी खसरा नम्बर 549 रकबा 0.16 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 80/-रूपये अर्थदण्ड एवं 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व साक्ष्यों के विपरीत होने से काबिल निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई जवाबदेही का कोई अवसर नहीं देकर मात्र हल्का पटवारी की झूठी रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है ना ही कोई सरकारी तावान बकाया है। अधीनस्थ न्यायालय ने एकपक्षीय आदेश पारित में विधिक त्रुटि की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 8.10.2015 निरस्त किये जाने की इस्तदुआ की गयी।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जयें सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट व परोकार सरकार सुनी गयी।



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

है। कब्जा छोड़ दिया है तथा भविष्य में उक्त आराजी पर कभी अतिचार नहीं करेगा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट पर विश्वास करके पूर्ण धारणा बनाकर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानकर सजायाब किया गया है। पत्रावली में पश्चात्वर्ती बाबत कोई रेकार्ड व साक्ष्य मौजूद नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं माना जा सकता। वर्तमान में विवादित आराजी खाली पडी हुयी है। उसके विरुद्ध कोई तावान राशि भी बकाया नहीं है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 08.10.2015 निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत परोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की प्रोपर तामील करवाकर, विधिवत सुनवाई कर समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है इसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में अतिचार करने पर मि0नं0 307/14 निर्णय दिनांक 24.4.2015 से बेदखल किया गया है। अपीलांट आदतन अतिक्रमी है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व परोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। किन्तु बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का कथन रहा है कि उसने उक्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया है व भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रति सहानुभूति का रख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा आदेश दिनांक 8.10.2015 से पारित जप्ति, बेदखली एवं शास्ति के आदेश को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 1167/15 में पारित निर्णय दिनांक 08.10.2015 से दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित आराजी से कब्जा छोड़ दें तथा तहसीलदार, बारां के समक्ष दो माह में उपस्थित होकर अण्डरटेंकिंग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे तथा तहसीलदार, बारां कब्जा छोड़ने से संतुष्ट हो जावे तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा निर्णय दिनांक 8.10.2015 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.10.2015 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 30.07.2018 को सरे इजलास निश्चाया जाकर सुनाया गया।

